[श्री शीलभद्र याजी]

कतिपय सदस्यों ने सरकार को चेतावनी दी है खाद्य नीति के बारे मे और समाजवादी नीति के बारे मे । हमारी जो ढुलमुल नीति है उसका परित्याग करना पडेगा । इसलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देते हुए हमको खेद के साथ कहना पडता है कि राष्ट्रपति ने जो हमारी सरकार की मूल नीति है ससद मे बताई हुई नीति है समाजवादी राज बनाने की उसके बारे मे जिक्र तक नही किया । जब दोनो सदनो के सामने राष्ट्रपति भाषण देते है तो सरकार की जो मूल नीति है उसके बारे मे उल्लेख भी नही करते कि समाजवादी व्यस्था बनाने मे समाजवादी राज बनाने मे हमारी सरकार क्या करने जा रही है । ठीक है कि इतने बरसों के बाद हम दूसरे देशो से गल्ला नही लेगे मदद नही लेगे लेकिन इसके साथ साथ उनको बताना चाहिए था कि हमारी सरकार समाजवादी व्यवस्था कायम करने के लिए ये-ये रास्ते लेगी ये-ये कदम उठाएगी । यह राष्ट्रपति के भाषण मे एकदम नही है । इसलिये हम सरकार को बताना चाहते है है कि काग्रेस सरकार को समाजवाद की स्थापना की नीति अपने सामने रखनी पड़ेगी । इस सदन मे और बाहर हम बारबार कहते रहे है कि अब ज्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं है । सब लोगो की यह माग है । जनता की भी माग है वोटर की माग है कि जल्दी से जल्दी जो इस देश मे गरीबी है उस गरीबी का उन्मूलन हो । हो सकता है कि जब समाजवादी व्यवस्था कायम हो तो दल भी सहयोग करे । इसलिए सरकार की जो ढुलमुल नीति है वह समाप्त हो । समाजवाद की जो धीमी रफ्तार है उसको तेज करना पडेगा और 1970 तक इस देश मे समाजवादी रिपब्लिक बनाने की नीति सरकार को घोषित करनी चाहिए । जो सविधान है कास्टीट्यूशन है उसमें रेडीकल अमेडमेट, सशोधन करने की जरूरत है । जो कलकारखाने बेसिक इन्डस्ट्रीज है बैक है उन सबका जल्दी जल्दी सरकार को राष्ट्रीयकरण करना चाहिए । जितने गवर्नमेट मुलाजिम है वे सब खिलाफ हो गए कि जैसे भी करो सरकार को गिराओ चूकि महगाई भत्ता नही देती । उनकी पढाई-लिखाई का इन्तजाम नही करती है । इसलिए यदि ज्यादा से ज्यादा बैको का, कारखानो का और बाकी चीजो का समाजीकरण करेगी तो उसके पास इतना धन हो जायेगा कि उसे अमरीका के पास रूस के पास जाने की जरूरत नही रहेगी । जो सरकारी मुलाजिम हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा भत्ता देकर खुशकर सकती है । इसलिए सरकार को जल्दी से जल्दी 1970 तक इन्डिया को सोशलिस्ट रिपब्लिक डिक्लेयर करके इन सब चीजो का राष्ट्रीयकरण करने की रफ्तार तेज करनी चाहिए । वोटरों ने जो चेतावनी दी है उसके मुताबिक आप समाजवादी व्यवस्था कायम करिए और आर्थिक दशा सुधारिए । मै काग्रेस पार्टी की बात नही कर रहा हूं हमारे हिन्दुस्तान की जो 50 करोड जनता है जो उनको दुख है तकलीफ है जो गरीबी है बेकारी है उन सब चीजो का समाधान रामबाण औषधि है समाजवादी व्यवस्था । उसके लिए हमारे राष्ट्रपति ने अपने भाषण मे कोई जिक्र नही किया । उनको जिक्र करना चाहिए था कि जल्दी से जल्दी समाजवादी व्यवस्था कायम की जाय भले ही स्वतत्र पार्टी के लोग चिल्लपो मचाते रहे । धीमी रफ्तार से चलने वाली समाजवाद की गाडी को तीव्र करना पडेगा यही हमारी सरकार से प्रार्थना है ।

श्री लोकनाथ मिश्र लोगो ने आपको वोट नही दिया इसलिए समाजवादी ढाचे की बात करने है ।

श्री शीलभद्र याजी आपको उठाकर फेक देगे ।

ALLOCATION OF TIME FOR GOVERNMENT BUSINESS

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have to inform Members that the Business Advisory Committee at its meeting

held today has recommended allocation of time for Government business as follows:

Government Business	*Time Allotted*	
1. General discussion on the General Budget for the year 1967-68	1 day	(28-3-1967)
2. General discussion on the Railways Budget for the year 1967-68	4 hours	(29-3-1967)
3. General discussion on the Goa, Daman and Diu Budget for the year 1967-68	1 hour	(29-3-1967)
4. Consideration and return of the Appropriation Bills relating to the following :— (*a*) Demands on Account (General) for 1967-68. (*a*) Supplementary Demands for Grants (General) for 1966-67 (*c*) Demands on Account (Railways) for 1967-68 (*d*) Supplementary Demands for Grants (Railways) for 1966-67 (*e*) Demands on Account (Goa, Daman and Diu) for 1967-68 (*f*) Supplementary Demands for Grants (Goa, Daman and Diu) for 1966-67	1 day	(30-3-1967)
5. General discussion on the Rajasthan Budget for 1967-68 6. Consideration and return of the Appropriation Bills relating to the following : — (*a*) Demands on Account (Rajasthan) for 1967-68 (*b*) Supplementary Demands for Grants (Rajasthan) for 1966-67 7. The Armed Forces (Special Powers) Continuance Bill, 1967	1 day	(30-3-1967)
8. Motion regarding Proclamation issued under article 356 of the Constitution in relation to the State of Rajasthan	1 day	(3-4-1967)
9. Short duration discussion under Rule 176 regarding disclosures contained in the Book "The Untold Story" by Lt. General B. M. Kaul	2 hours	

In order to be able to complete the business, the Committee further recommended that the House might curtail or dispense with the lunch recess and sit up to 6.00 P.M. on all the days up to the 31st March, 1967.

---

3 P.M.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—*contd.*

SHRI M. N. KAUL (Nominated): Madam Deputy Chairman, I should like to make a few suggestions arising out of the crisis in Rajasthan. I have had the advantage of listening to the debates in this House and also of following the debates in the other House. There have been many speeches, but the facts lie within a narrow compass. The election results were completed on 25th February. The Assembly was dissolved on the 28th February. So, it was open to the Governor on the 1st of March to summon the leader of the Congress Party, which was the largest single Party in the Assembly to form a Government. If he had done so, that would have been in accordance with constitutional practice. The Congress Party did not have a clear majority, but it was the largest single Party. The Governor would have been perfectly in order to ask Mr. Sukhadia to form the Government, but he adopted the alternative course, which had also the sanction of constitutional precedents. In England when no Party has a clear majority in the House of Commons, the King must then use his own judgment as to which leader he would summon, subject only to the condition that the person summoned must be able to command a majority by some coalition or compromise with the other Parties. So, the Governor met